आपराधिक विविध

माननीय न्यायाधीश के. एस. तिवाना के समक्ष

जरनैल सिंह, आदि, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य, - उत्तरदाता।

1975 का आपराधिक विविध संख्या **2687**।

में **1975** का आपराधिक विविध संख्या **562**।

5 मार्च, 1976।

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) - धारा 167 (2) परंतुक, 209 और 437 (5) - धारा 167 (2) के परंतुक के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए गए आरोपी - ऐसी जमानत - क्या अध्याय XXXIII के तहत जमानत के बराबर माना जाना चाहिए - आरोपी को करते समय मजिस्ट्रेट - क्या जमानत रद्द करने का अधिकार है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के परंतुक (ए) में प्रावधान किया गया है कि धारा 167 के तहत अभियुक्त को दी गई जमानत संहिता के अध्याय XXXIII के तहत दी गई जमानत के समान है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, इसे उस अध्याय के तहत जमानत के रूप में लिया जाना चाहिए और धारा 167, इसलिए, जमानत के मामले में अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं रखती है, बल्कि अध्याय XXXIII के प्रावधानों में खुद को विलय करती है। संहिता की धारा 167 संहिता की धारा 437 (1) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का विस्तार है। धारा 209 (बी) के प्रावधानों द्वारा शक्तियों के इस तरह के विस्तार को कम नहीं किया जा सकता है, जब सक्षम धारा, अर्थात धारा 167, यह प्रावधान करती है कि इसे संहिता के अध्याय XXXIII के तहत जमानत माना जाएगा। धारा 209 (बी) की व्याख्या अध्याय XXXIII के प्रावधानों के अधीन की जानी है जिसमें जमानत लेने के बारे में प्रावधान हैं और इसमें आवश्यक रूप से संहिता की धारा 437 (5) शामिल है। यह उपधारा मजिस्ट्रेट को केवल उसी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अधिकार देती है, जिसे उसके द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है और इसलिए, मजिस्ट्रेट को एक आरोपी बनाते समय जिसे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है, उसकी जमानत रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है।

(पैरा 6 और 7)।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत आवेदन में अनुरोध किया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति एमआर शर्मा द्वारा 24 फरवरी, 1975 के आदेश के तहत दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कृपाल सिंह, वकील।

प्रतिवादी की ओर से देविंदर सिंह बाली, एडवोकेट।

निर्णय

न। कुलविंट सिंह तिवाना (मौखिक) :

1. जरनैल सिंह, जोगिंदर सिंह, करमन सिंह चार अन्य लोगों के साथ 25 सितंबर, 1974 को हिसार जिले के शमशाबाद गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी हैं। जरनैल सिंह और करमन सिंह को 26 सितंबर, 1974 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि जोगिंदर सिंह को 1 अक्टूबर, 1974 को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान पेश नहीं किया, जिसके पास प्रतिवादियों की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर मामला करने का अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत प्रतिवादियों की रिहाई की मांग करने वाले एक आवेदन को मजिस्ट्रेट के साथ-साथ हिसार के सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। जरनैल सिंह, जोगिंदर सिंह और करमन सिंह ने इस अदालत में जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे ***जरनैल सिंह और दो अन्य बनाम हरियाणा राज्य के रूप में दर्ज किया गया था।***[1] एम. आर. शर्मा, जे. ने इन तीन प्रतिवादियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

2. जमानत पर रिहा होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान पेश करते समय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं रखा। चूंकि अभियोजन एजेंसी अपराध में प्रतिवादियों की भागीदारी के बारे में संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट के कॉलम नंबर 3 में अपने नाम दिखाए। चालान पेश करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरसा ने प्रतिवादियों और उनके सह-अभियुक्तों को मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय में पेश किया, लेकिन उन्हें जमानत पर रहने की अनुमति दी। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर प्रतिवादियों की जमानत रद्द करने के लिए हिसार के सत्र न्यायाधीश का रुख किया कि विद्वान कमिटिंग मजिस्ट्रेट उनकी जमानत रद्द करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए कानून द्वारा बाध्य थे। आवेदन के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन प्रतिवादियों को जमानत पर सत्र न्यायालय में ले जाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया। सत्र न्यायाधीश हिसार ने 7 जून, 1975 के अपने आदेश के तहत जमानत रद्द करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि प्रतिवादियों को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था, इसलिए उनके पास इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया । ***रेक्स,***[2] और जगदीश कुमार बनाम जगदीश कुमार ***मामले में इस न्यायालय का एक असूचित निर्णय/लाल चंद***[3] का फैसला जिंद्रा लाल जे ने किया। इसी तरह की परिस्थितियों में, जैसा कि मामले में है, जिंद्रा लाल जे ने मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर किए गए आरोपियों की जमानत रद्द नहीं की, यह देखते हुए कि *सियोती के मामले* (सुप्रा) में निर्णय *प्रथम दृष्टया* सही कानून निर्धारित करता है। हरियाणा राज्य ने अब सत्र न्यायाधीश के दिनांक 9 जून, 1975 के आदेश के विरुद्ध उसी आधार पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें जमानत रद्द करने की बात कही गई थी। यह आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने जमानत बांड की शर्तों का दुरुपयोग किया था या जमानत की रियायत की जब्ती के लिए खुद को उजागर करते हुए गलत आचरण किया था।

---

[1] सी.आर.एम. 562-एम/75 पर 24 फरवरी, 1975 को निर्णय लिया गया।

[2] ए.आई.आर. 1948 इलाहाबाद 368.

[3] सीआर 952/68 का फैसला 11 सितंबर, 1968 को हुआ था।

3. मैंने पक्षकारों के वकीलों को काफी विस्तार से सुना है। 24 फरवरी, 1975 को इस न्यायालय द्वारा पारित जमानत का आदेश धारा 167 (2) (ए), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के प्रावधानों के तहत था क्योंकि जांच एजेंसी इस धारा में प्रदान की गई 60 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर चालान पेश करने में विफल रही थी। हरियाणा राज्य की ओर से पेश श्री डी एस बाली ने आग्रह किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 209 (बी) उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनमें मजिस्ट्रेट को आरोपी को दोषी ठहराना होता है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भी इस तर्क का समर्थन करने के लिए कानून के इस प्रावधान के खिलाफ तर्क दिया है कि यह धारा प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट को परिस्थितियों में रखे गए अभियुक्तों की जमानत रद्द करने का अधिकार नहीं देती है जैसा कि इस मामले में प्रतिवादी हैं।

4. पक्षकारों के वकील द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं पर चर्चा में प्रवेश करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 167 और 209 के प्रासंगिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैं: –

"167 (1) * ** * *

2 * *** * ।

बशर्ते कि -

(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पंद्रह दिनों की अवधि के बाद पुलिस की हिरासत के अलावा अन्यथा हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत अभियुक्त व्यक्ति को साठ दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, और साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर, आरोपी

1. सीआर 952/68 पर 11 सितंबर, 1968 को फैसला सुनाया गया,

यदि व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा, और *इस धारा के तहत* जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति *को उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा माना जाएगा।*

1. जब पुलिस रिपोर्ट या अन्यथा स्थापित किसी मामले में, अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, तो वह-

    1. * **

2. जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अभियुक्त को मुकदमे के दौरान और सुनवाई के समापन तक हिरासत में भेजना;

* * * * * "

5. दंड प्रक्रिया संहिता (1898) के अंतर्गत विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंपे जाने वाले मामलों में जमानत के मामलों में मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित दो प्रावधान थे; एक धारा 207-ए (16) के रूप में पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों में था और दूसरा शिकायत पर स्थापित मामलों में उस संहिता की धारा 220 के रूप में था। धारा 207-ए (16) और 220 के स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता (1898) के निरसन के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता (1973) में धारा 209 अधिनियमित की गई है। प्रतिवादियों के वकील श्री कृपाल सिंह ने तर्क दिया है कि पुरानी संहिता की धारा 207-ए (16) और 220 में "जमानत लेने के संबंध में इस संहिता के प्रावधानों के अधीन" शब्दों के स्थान पर विधायिका द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 209 (बी) में "जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन" शब्दों का प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, नए प्रावधान ने उन मामलों में जमानत के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियों को बढ़ा दिया है जो सत्र न्यायालय में किए जाने हैं।

6. जब अध्याय XXXIII, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के प्रावधानों के प्रकाश में विचार किया जाता है, जो जमानत के संबंध में न्यायालयों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो विद्वान वकील का तर्क बिना किसी बल के प्रतीत नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 167 के परंतुक (क) में प्रावधान है कि धारा 167 के तहत अभियुक्त को दी गई जमानत उसी स्तर पर है जिस स्तर पर अध्याय XXXIII, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के तहत दी गई जमानत है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, इसे उस अध्याय के तहत जमानत के रूप में लिया जाना चाहिए। धारा 167, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973), इसलिए, जमानत के मामले में अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं रखती है, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के अध्याय XXXIII के प्रावधानों में खुद को विलय करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 167, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 437 (1) के तहत अपनी शक्तियों पर लगाए गए सीमा के बावजूद हिरासत में किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का विस्तार है। धारा 209 (बी) के प्रावधानों द्वारा शक्तियों के इस तरह के विस्तार को कम नहीं किया जा सकता है, जब सक्षम धारा, अर्थात धारा 167, यह प्रावधान करती है कि इसे संहिता के अध्याय XXXIII के तहत जमानत माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 209 (बी) में "जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता (1898) की धारा 207-ए (16) और 220 के शब्दों की तुलना में लचीले हैं। भाषा से पता चलता है कि धारा 209 (बी) की व्याख्या अध्याय XXXIII के प्रावधानों के अधीन की जानी है जिसमें जमानत लेने के बारे में प्रावधान हैं, अर्थात धारा 436, 437 और 439। इसमें आवश्यक रूप से इस संहिता की धारा 437(5) भी शामिल है। जब ऐसी स्थिति होती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ऐसे मामलों पर उप-धारा (5) सहित पूरी ताकत के साथ लागू होगी। दंड प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 437 (5) निम्नानुसार है: –

> "कोई भी न्यायालय जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए।"

यह उप-धारा मजिस्ट्रेट को केवल उस व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अधिकार देती है, जिसे उसके द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। उस स्थिति

में प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट के पास उन प्रतिवादियों की जमानत रद्द करने की कोई शक्ति नहीं थी, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था।

7. हरियाणा राज्य की ओर से पेश श्री बाली ने तर्क दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 उस संहिता की धारा 437 से भिन्न है। यह एक अनिवार्य रूप में किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए केवल मजिस्ट्रेट में शक्ति का निवेश करता है यदि कानून के इस प्रावधान में उल्लिखित परिस्थितियां किसी मामले में मौजूद हैं। इससे उन्होंने आगे आग्रह किया है कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को उच्च अधिकार क्षेत्र के न्यायालय नहीं माना जाना चाहिए जब ये न्यायालय धारा 167, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के तहत जमानत की अनुमति देते हैं। मैं राज्य के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दी गई जमानत को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के अध्याय XXXIII के तहत माना जाता है। सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत जमानत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 की सहायता से होगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (5) इन परिस्थितियों में जमानत रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों को नियंत्रित करेगी। इस उप-धारा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के खंड (बी) के प्रतिबंधात्मक भाग के भीतर पढ़ा जाना है।

8. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत प्रतिवादी को जमानत रद्द नहीं करने का औचित्य था। राज्य के वकील ने आगे आग्रह किया कि इस मामले में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने अपराध की वीभत्स प्रकृति को देखते हुए जमानत रद्द करने का आग्रह किया। यहां तक कि एक स्तर पर मामले की जांच करने वाली वैधानिक रूप से गठित एजेंसी को भी प्रतिवादियों पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं मिला, जिसके लिए उन्हें शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा आरोपी बनाया गया था और इस तथ्य को एमआर शर्मा, जे द्वारा 24 फरवरी, 1975 को प्रतिवादियों को जमानत देते समय ध्यान में रखा गया था। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादियों ने किसी भी तरह से उन्हें दी गई जमानत की रियायत का दुरुपयोग किया हो। जमानत रद्द करने के लिए राज्य के आवेदन को स्वीकार करने के लिए कोई परिस्थिति नहीं पाते हुए, याचिका खारिज कर दी जाती है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी